THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/374

दिनांक : 05.08.2026

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : भारत-कनाडा एफटीए के तहत प्रस्तावित रूल्स ऑफ ओरिजिन (आरओओ)/टैरिफ लिबरलाइजेशन पर तत्काल इनपुट*

यह आज भारत-कनाडा FTA चर्चाओं के संबंध में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC) के साथ हुई बैठक को संदर्भित करता है, जिसमें हमें उपरोक्त मामले पर इनपुट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

जैसा कि बताया गया है, कनाडाई पक्ष ने HS कोड 3916, 3917, 3920 और 3921 के तहत उत्पादों के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल (PSR) के रूप में CTSH का प्रस्ताव दिया है। HS कोड 3918 से 3926 (3920 और 3921 को छोड़कर) के तहत शेष उत्पादों के लिए, चर्चा के तहत प्रस्तावित नियम CTSH + 25% मूल्य संवर्धन (VA) है।

टैरिफ उदारीकरण के संबंध में (ITC(HS) कोड 39 चैप्टर के तहत 262 आइटम, जैसा कि DCPC द्वारा हमें बताया गया है), यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के पास विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक मूल्य वर्धित उत्पादों (Hs कोड 3916 से 3926) में पर्याप्त घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस है इसके अलावा, यह सेक्टर ज़्यादातर MSME पर चलता है और इसे सही टैरिफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए, हमारा सुझाव है कि टैरिफ में छूट पर धीरे-धीरे विचार किया जा सकता है।

इसे देखते हुए, हम आपके देखने और सलाह (अगर कोई हो) के लिए 262 आइटम की https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260805023806.xlsx

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ओरिजिन/कंसेशन के प्रपोज़्ड रूल्स को देखें और अगर कोई हो तो अपने कमेंट्स/सुझाव **कल दोपहर 12:00 बजे तक** nilotpal@plexconcil.org और bharti@plexconcil.org पर शेयर करें , ताकि काउंसिल इंडस्ट्री

के फीडबैक को इकट्ठा कर सके और उसे तय टाइमलाइन के अंदर डिपार्टमेंट को सबमिट कर सके।

मेंबर्स से यह भी रिक्वेस्ट है कि वे काउंसिल को उन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड (TBTs) के बारे में बताएं जिनका वे अभी कैनेडियन मार्केट में सामना कर रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग, कन्फर्मिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स, या मार्केट एक्सेस में कोई और रुकावटें शामिल हैं। यह जानकारी काउंसिल को चल रही इंडिया-कनाडा FTA बातचीत के दौरान सरकार के साथ इन चिंताओं को उठाने में मदद करेगी।

सादर।

PLEXCONCIL टीम